>

Title: Need to release funds on priority for disbursal of scholarships to OBC students in Maharashtra.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): केंद्र सरकार ने ओ.बी.सी. छात्रों के लिए शुरू किये छात्रवृत्ति परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन लगभग बंद कर दिया है । इसलिए महाराष्ट्र राज्य के ओ.बी.सी. छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक शुल्क के बारे में कठिनाइयाँ आ रही हैं और उनकी पढ़ाई में तकलीफ हो रही है। केंद्र सरकार ने 1998 से देश के सभी राज्यों के ओ.बी.सी. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति परियोजना शुरू की इसके अनुसार राज्य सरकारें द्वारा पहले खर्च करने के बाद केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी । लेकिन परियोजना के अनुसार केंद्र सरकार ने समुचित धनराशि का आवंटन नहीं किया । महाराष्ट्र राज्य द्वारा ओ.बी.सी. छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए खर्च किये गरीब 1400 करोड़ रूपये की बकाया राशि अभी तक नहीं दी गयी है । इससे ओ.बी.सी. छात्रों के साथ राज्य सरकार, शैक्षिक संस्थाओं में 2011-12 शैक्षिक वर्ष में करीब 4 लाख ओ.बी.सी. छात्रों को छात्रवृत्ति परीक्षा शुल्क और शैक्षिक संस्थाओं को दिये जाने वाले शुल्क के रूप में लगभग 400 करोड़ रूपये देने हैं । लेकिन केंद्रीय आर्थिक सहायता के अभाव में राज्य सरकार धनराशि कहां से जुटाये ऐसा प्रश्नचिन्ह लगा है । ओ.बी.सी. छात्रों के छात्रवृत्ति परियोजना में राज्य सरकार के आर्थिक आवंटन को लंबित रखने से हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार महाराष्ट्र राज्य के ओ.बी.सी. छात्रों की छात्रवृत्ति की लंबित धनराशि तत्काल निर्गत करे और भविष्य में ओ.बी.सी. छात्रों छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने के लिए भी अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दे । सरकार ओ.बी.सी. छात्रों के शैक्षिक कार्य के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठायेगी ऐसी अपेक्षा करता हूं ।